विशेषज्ञ की राय

पिछड़े क्षेत्रों में विकास व औद्योगिकीकरण को मिलेगी रफ्तार

आद्या प्रसाद पांडेय

पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग बीएचयू व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन

बजट में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कोशिश के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की इच्छाशक्ति भी दिखती है। युवाओं के रोजगार और किसानों की समृद्धि की विशेष चिंता की गई है। बजट प्रावधान जमीन पर उतरे तो प्रदेश के खासकर पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थापना और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी।

जिस प्रकार से स्टार्टअप और कृषि सेक्टर को प्रोत्साहित करने पर फोकस है, उससे स्पष्ट है कि अमल हुआ तो युवाओं और किसानों की कुंठा दूर होगी और रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी

रुकेगा। वैश्विक निवेश सम्मेलन में हुए एमओयू और इसके लिए बजट में किए गए प्रावधानों के जमीन पर उतरने से जीडीपी के साथ ही विकास दर में उछाल आएगा। बेरोजगारी दर भी कम होगी।

बजट में अवस्थापना, सामाजिक सुरक्षा, एमएसएमई, एयर कनेक्टिविटी, बिजली उत्पादन, पर्यटन विकास समेत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सभी सेक्टरों के विकास का ख्याल रखा गया है। इससे समाज के शीर्ष से लेकर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की चिंता झलकती है। बजट में संतुलित तरीके से कुछ नई घोषणा करके सरकार ने यह भी जताने का प्रयास किया है कि वह पहले से चल रही योजनाओं को भी पूरा कराने के लिए संकल्पित है। चुनावी संकल्पों को पूरा करने को लेकर भी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने की घोषणा इसी दिशा में एक कदम है।

पूर्वांचल के विकास पर और ध्यान देने की जरूरत

पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार ने बजट में भले ही 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, लेकिन वर्षों से पिछड़े इस इलाके के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुए है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अति पिछड़े इलाकों में भी कल-कारखाने लगाने को लेकर पहल की जरूरत है। पूर्वांचल में अवस्थापना विकास को लेकर भी अभी बहुत काम करना होगा।